



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2007/फाल्गुन 18, 1928

No. 65]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2007/PHALGUNA 18, 1928

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2007

जांच शुरुआत

(निर्णायक समीक्षा)

**विषय :** कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉस्टिक सोडा के आयातों पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा की शुरुआत

सं. 15/03/2007-डीजीएडी.—जबकि 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 18 जनवरी, 2000 की अधिसूचना द्वारा अन्तिम शुल्क लागू करने की सिफारिश की है तथा दिनांक 27 मार्च, 2002 की अधिसूचना सं. 32/2002 के द्वारा भारत सरकार द्वारा अन्तिम पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था। प्राधिकारी ने दिनांक 7-10-2002 की अधिसूचना द्वारा कतर के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कॉस्टिक सोडा (जिसे एतेदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा जाएगा) के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हुए अंतिम जांच परिणाम जारी किए थे और दिनांक 31-10-2002 की अधिसूचना सं. 121/2002 के द्वारा भारत सरकार द्वारा निश्चयात्मक शुल्क लगाया गया था।

## 2. समीक्षा के लिए अनुरोध

और जबकि सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 के संदर्भ में यदि लागू पाटनरोधी शुल्क को पहले ही हटा नहीं लिया जाता है तो वह लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् समाप्त हो जाएगा।

नियमों के तहत निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निरंतर पाटनरोधी शुल्क लगाने की जरूरत की समय-समय पर समीक्षा किया जाना अपेक्षित है और प्रत्येक से प्राप्त सूचना के आधार पर यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के शुल्क के सतत अधिरोपण को जारी रखने का औचित्य नहीं है तो प्राधिकारी केन्द्र सरकार को शुल्क समाप्त करने की सिफारिश कर सकता है उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के आधार पर शुल्क की समाप्ति की तारीख से पहले उचित समय-सीमा के भीतर समीक्षा किया जाना उचित है कि शुल्क के समाप्त होने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है या नहीं।

उपर्युक्त प्रावधानों के संदर्भ में, मै. अल्कली मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो सभी भारतीय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व कर रही है और संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादन में जिसका प्रमुख हिस्सा है, ने प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समीक्षा करने हेतु विधिवत प्रमाणों सहित एक याचिका प्रस्तुत की है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का मानना है कि पाटन को समाप्त करने के लिए ऐसे शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता और इस बात की जांच करने के लिए कि यदि शुल्क को समाप्त कर दिया जाता है अथवा उसमें परिवर्तन किया जाता है अथवा दोनों कर दिए जाते हैं तो क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है लागू पाटनरोधी शुल्क को निर्णायक समीक्षा कार्यवाहियों की शुरुआत करना उचित है।

### 3. समीक्षा का आधार

इस आधार पर कि कतर (जिसे एतदुपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) से पाटन जारी रहा है और उपाय के समाप्त होने से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया गया है।

आवेदक ने अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया है कि कतर से निर्यातकों एवं उत्पादकों ने भारतीय बाजार में वस्तु का पाटन जारी रखा है और वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद यह मात्रा काफी अधिक है। अतः यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क को वापस ले लिया जाता है तो पाटन और अधिक बढ़ जाएगा।

आवेदक ने आगे दावा किया है कि कतर में संबद्ध वस्तुओं की मौजूदा मात्रा उनकी घरेलू मांग से काफी अधिक है और दूसरे देशों को सामग्री का निर्यात पाटित कीमतों पर किया जा रहा है जिससे पाटनरोधी शुल्क को हटा लिए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना बढ़ जाती है।

### 4. जांच प्रारंभ

घरेलू उद्योग द्वारा समीक्षा की आवश्यकता के संबंध में प्रस्तुत सकारात्मक साक्ष्यों के आधार पर प्राधिकारी संतुष्ट होकर अधिनियम की धारा 9 क (5) के अनुसार इस बात की जांच करने के लिए समीक्षा प्रारंभ करते हैं कि वर्तमान शुल्क को हटा लेने से घरेलू उद्योग को पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं।

### 5. विचाराधीन उत्पाद

मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद कॉस्टिक सोडा है। कॉस्टिक सोडा (सोडियम हाइड्रॉक्साइड) एक अकार्बनिक रसायन है जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के तहत वर्गीकृत किया गया है। कॉस्टिक सोडा एक ज्ञात, अत्यधिक क्षारीय गंधरहित तरल है जिसका उपयोग कच्ची सामग्री अथवा एक सहायक रसायन के रूप में विविध औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है। इसका उपयोग प्रमुखतः लुदी एवं कागज, अखबारी कागज, विस्क्स यार्न, स्टेपल फाइबर, एल्यूमीनियम, सूत, वस्त्र, नहाने एवं कपड़े धोने के साबुनों, प्रक्षालकों, रंजक सामग्री, औषध एवं भेषजों, वनस्पति के विनिर्माण, पेट्रोलियम शोधन इत्यादि में किया जाता है। कॉस्टिक सोडा का उत्पादन दो स्वरूपों में किया जाता है—द्रव्य और ठोस। ठोस कॉस्टिक सोडा पपड़ी, प्रिल्स, दानों अथवा अन्य किसी स्वरूप में हो सकता है। कॉस्टिक सोडा के सभी स्वरूप उत्पाद के कार्य क्षेत्र में आते हैं। चूंकि यह उत्पाद की निर्णायक समीक्षा है जिस पर शुल्क पहले से लागू है इसलिए विचाराधीन उत्पाद अपरिवर्तित रहेगा।

### 6. क्रियाविधि

इस जांच से यह निर्धारित हो सकेगा कि वर्तमान में लागू पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने से पाटन एवं क्षति के जारी रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है अथवा नहीं।

- (i) समीक्षा में दिनांक 7-10-2002 की अधिसूचना सं. 55/1/2001-डीजीएडी के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा;
- (ii) इस जांच में शामिल देश कतर है;
- (iii) वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1-1-2006 से 31-12-2006 तक होगी;
- (iv) उपर्युक्त नियमावली के नियम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 और 20 के प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों सहित इस समीक्षा पर लागू होंगे।

#### 6.1 सूचना प्रदान करना

संबद्ध देशों में निर्यातकों, भारत स्थित दूतावास के जरिए कतर सरकार को, उत्पाद से संबंधित भारत के ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को अलग से लिखा जा रहा है कि वे संगत सूचना निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से प्रस्तुत करें और प्राधिकारी को

निम्नलिखित पते पर अपने विचारों से अवगत कराएं :

निर्दिष्ट प्राधिकारी,  
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय,  
भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
वाणिज्य विभाग,  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011

अन्य कोई हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समयावधि के भीतर निर्धारित प्रपत्र में और निर्धारित ढंग से जांच से संबंधित अनुरोध कर सकता है।

## 6.2 समय-सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना तथा सुनवाई के लिए कोई अनुरोध प्राधिकारी को उपर्युक्त पते पर इस समीक्षा अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस (40) दिनों के भीतर पहुंच जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपर्युक्त नियमों के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम रिकार्ड कर सकते हैं।

## 6.3 अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के संदर्भ में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की राय में सूचना को सारांश में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है तो इसके कारण दर्शाने का एक विवरण प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है या उचित समय के भीतर उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्रीय सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

## 6.4 सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

कोई हितबद्ध पक्षकार नियम 6(7) के संदर्भ में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

क्रिस्टी एल. फेर्नांडेज, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 9th March, 2007

## Initiation

(Sunset Review)

**Subject : Initiation of Sunset Review anti-dumping investigation concerning imports of Caustic Soda originating in or exported from Qatar**

**No.15/03/2007-DGAD.**—Whereas the Designated Authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Duty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, recommended imposition of provisional duty *vide* notification dated 18th January, 2002 and provisional duty was imposed by the Government of India *vide*, notification No. 32/2002, dated 27th March, 2002. The Authority issued its Final findings recommending imposition of definitive Anti Dumping Duty on imports of Caustic Soda (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from Qatar, *vide* notification dated 7-1-2002 and definitive duty was imposed by the Govt. of India *vide* Notification No. 121/2002, dated 31-10-2002.

## 2. Request for review

And whereas in terms of the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 the anti-dumping duty imposed shall unless revoked earlier, cease to have effect on expiry of five years from the date of such imposition.

And whereas the Rules supra require the Authority to review from time to time, the need for continued imposition of Anti Dumping Duty and if it is satisfied, on the basis of information received by it that there is no justification for continued imposition of such duty, the authority may recommend to the Central Government for its withdrawal. Notwithstanding the above provision the authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry, within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

In terms of the above provisions, M/s. Alkali Manufacturers Association of India, the Association representing the Indian producers, commanding a major proportion of the domestic production of the subject goods, has approached the authority with a duly substantiated petition requesting for such a review, the Designated Authority considers that initiation of sunset review proceedings for the Anti Dumping Duty in force would be appropriate to examine the need for continued imposition of such duty to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were remove or varied or both.

## 3. Grounds for review

The request is for continuation of the anti-dumping duties in force based on the grounds that dumping has continued from Qatar (herein after referred as the subject country) and the expiry of the measure would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

The applicant has *inter alia* claimed that the exporters and producers from Qatar have continued to dump the goods in the Indian market and volume is also significant, in spite of anti-dumping duty in force. Therefore, dumping would be intensified should the present anti-dumping duty be revoked.

The applicant further claims that the existing capacities of the subject goods in Qatar far exceed their domestic demands and material is being exported to other countries at dumped prices, which increases the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury once the anti-dumping duty is removed.

## 4. Initiation

Having satisfied itself, on the basis of the positive evidence submitted by the domestic industry substantiating the need for a review, the Authority hereby initiates a review in accordance with Section 9 A (5) of the Act, to examine whether cessation of the duty in force would lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.

## 5. Product under consideration

The product under consideration in the original investigation was Caustic Soda. Caustic Soda (Sodium Hydroxide), which is an inorganic Chemical, classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act. Caustic Soda is a soapy, strongly alkaline odorless liquid widely used in diverse industrial sectors, either as a raw material or as an auxiliary chemical. It is mainly used in the manufacture of pulp and paper, newsprint, viscose yarn, staple fiber, aluminum, cotton, textiles, toilet & laundry soaps, detergents, dyestuffs, drugs and pharmaceuticals, vanaspati, petroleum refining etc. Caustic soda is produces in two forms - lye and solids. Solids can be in the form of flakes, prills, granules or any other form. All forms of caustic soda are within the scope of the product. This being a sunset review of the product against which duty is already in force the product under consideration shall remain unchanged.

## 6. Procedure

The investigation will determine whether the cessation of the duty in force is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

- (i) The review will cover all aspects of Notification No. 55/1/2001-DGAD, dated 7-1-2002;
- (ii) The country involved in this investigation is Qatar;
- (iii) The period of investigation for the purpose of the present review is from 1-1-2006 to 31-12-2006;
- (iv) The provisions of Rules 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19 and 20 of the Rule supra shall be *mutatis mutandis* applicable in this review.

**6.1 Submission of Information:**

The exporters in subject country, the Government of Qatar through its embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the product and the domestic industry, are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority in the following address:

The Designated Authority  
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties  
Government of India  
Ministry of Commerce and Industry  
Department of Commerce,  
Udyog Bhavan,  
New Delhi-11 0011.

Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below.

**6.2 Time Limit:**

Any information relating to the present review and any request for hearing should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 Days) from the date of publication of this review notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Designated Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**6.3 Submission of information on Non-confidential basis:**

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-Confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summary, a statement of reason thereof is required to be provided. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

**6.4 Inspection of public file:**

Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties in terms of Rule 6 (7).

CHRISTY L. FERNANDEZ, Designated Authority

804 9707-2